हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य का विकास

भरत लाल

"अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा"

ऋग्वेद की यह सूक्ति हमें स्मरण कराती है कि युवा ही विश्व के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत की मध्य-आयु 29 वर्ष है और हमारी युवाशक्ति पूर्ण उभार पर है। तभी तो हमारे युवा भारत की गौरवमयी परम्परा को आगे बढ़ाने और भविष्य के निर्माण की दिशा में विविध मार्गों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इंडिया@2047 अर्थात् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 के भारत के विज़न के अनुसार उन्नत भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में युवाओं का सशक्तीकरण करना अत्यंत आवश्यक है।

भारत सरकार ने जीवन स्तर सुधारने और 'ईज ऑफ लिविंग' अर्थात् जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं जिनमें सभी के लिए आवास की सुनिश्चित व्यवस्था; पीने का साफ पानी; ग्रामीण विद्युतीकरण; रसोई गैस; इंटरनेट और संचार की सुविधाएं; स्वास्थ्य बीमा; सड़क संपर्क व्यवस्था; उत्तम शिक्षा; और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना शामिल है ताकि सभी एकजुट होकर अपने भविष्य के निर्माण पर ध्यान दे सकें और अपनी पूरी क्षमता से विकास कार्यों में सहयोग कर पाएं।

इस समय देश में कामकाज करने वाले 15 से 64 आयुवर्ग के लोगों की संख्या 80 करोड़ के आसपास है जो हमारी कुल जनसंख्या का करीब 67 प्रतिशत है। वर्ष 2020 से वर्ष 2050 को भारतीय अर्थव्यवस्था का 'स्वर्णकाल' माना जा रहा है जिसमें युवाओं की भूमिका मुख्य रहेगी; और सही नीतिगत उपाय अपनाए गए तो ये युवा लोग रचनात्मक बदलाव से भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार विविधता लाकर उच्च वृद्धि दर बनाए रखने में सफल होंगे। देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में मज़बूती से पकड़ बना रहा है और नवाचारों, स्टार्टअप्स और युवा शक्ति के सहारे वह न केवल अनेक विकसित देशों के लिए कड़ी स्पर्धा पेश कर रहा है बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने भी अपने उल्लेखनीय योगदान के बल पर एक विशेष पहचान बना ली है।

'टेकेड' का युग

देश के कार्यबल में हर वर्ष 1.2 करोड़ नए युवा बढ़ रहे हैं जिससे पता चलता है कि सभी के लिए कामकाज के अवसर जुटाने के साथ ही शिक्षा; कौशल; उद्यमिता; सार्वजनिक सेवाओं में सुधार; इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी सुविधाओं); डिजिटल टेक समन्वयन; श्रमिक संरक्षण और इन सबसे अहम ऐसी टिकाऊ हाट व्यवस्था बनाने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है जो देश की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के अनुरूप हो तथा सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने में सक्षम हो।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और दुनिया के हर दस यूनिकॉर्न में से एक भारत का होता है। स्टार्टअप इंडिया योजना और कारोबार की प्रक्रिया सरल बनाने के प्रयासों से ही इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की जा सकी है। जिस देश में 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे वहीं 2022 में इनकी संख्या 100 से ज्यादा हो जाना इस क्षेत्र में हुई महती सफलता को दर्शाता है। 2014 में भारत ने लगभग 4000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया था और 2022 में भारत द्वारा 15000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया जा चुका है। भारत ने नवाचारों के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ही तेजी से प्रगति की है। इस जबरदस्त कामयाबी का पता 'वैश्विक नवाचार इंडेक्स' देखने से लगता है क्योंकि जिस नवाचार सूची में 2015 में भारत का नाम 81वें स्थान पर था वहीं 2022 में भारत इस सूची में 40वें स्थान पर पहुँच गया।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन विज्ञान, शिक्षा, व्यावसायिक (प्रोफेशनल) सेवा, कृषि, खानपान जैसे 56

लेखक भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र के महानिदेशक हैं। ईमेल: ...gg@gov.in

विविध औद्योगिक क्षेत्रों में भारत के 656 ज़िलों में 77,000 से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप चल रहे हैं। ये नीतियां और सफलताएं भारत के स्पर्धात्मक वैश्विक मानकों के स्तर तक पहुँचने और देश के युवाओं के लिए 'अनुकूल पर्यावरण' विकसित करके ही संभव हो पाई है। उदाहरण के लिए बाज़ार तक पहुँच की व्यवस्था का अभाव स्टार्टअप्स के विकास में बहुत बड़ी बाधा थी और सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म के जरिए इसका आसानी से समाधान कर दिया। GeM पोर्टल ऑपरेटर-अनुकूल इंटरफेस बन चुका है जो उच्च क्वालिटी मानकों, बेहतर किस्म के उत्पादों, गोदाम और भंडारण सुविधाओं के नेटवर्क और माल लाने-ले जाने में लॉजिस्टिक सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराने की पूरी पक्की व्यवस्था की गारंटी देता है।

टिकाऊ स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में ऐसा ही एक और अहम पहलू है आंकड़ों, सेवाओं, बाजार सुविधाओं, उपभोक्ता तक पहुँच अर्थात् आउटरीच और कारोबार करने तथा नियमों का पालन करने की भारी लागत को कम करना। डिजिटल इंडिया देशभर के सुदूर क्षेत्रों को पहुँच में लाकर दूरी की बाधा के बावजूद सहयोग और समन्वय की क्षमता को बनाए रखने के लिए चलाया गया मिशन है। देश के आईटी और कंप्यूटर विशेषज्ञों के तालमेल से आईओटी क्रांति आई है जिससे भारतीय बाजार नए स्टार्टअप्स के लिए जोखिम का कारण बनने की जगह विश्व स्तर के आधुनिक, गतिशील और उन्नत बाजारों जैसे बन गए हैं।

रोज़गार के अवसर जुटाने वाले

विभिन्न दिशाओं में भारत की प्रगति का पता इस तथ्य से लग जाता है कि वह इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है; जहां 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर की थी वहीं यह 2019 में बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है और इसका लक्ष्य 2030-31 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह महत्वाकांक्षी विस्तार और वृद्धि तभी संभव होगी जब हमारी युवाशक्ति कौशल विकास, रोज़गार जुटाने की क्षमता बढ़ाने और विश्व बाज़ारों में पहुँच बनाने की दिशा में पक्के इरादे से जुट जाएगी।

सरकार ने कौशल विकास और युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं ताकि भावी कार्यबल के लिए दक्षता और बाजार-केंद्रित प्रतिभा तथा जानकारी की मज़बूत बुनियाद तैयार की जा सके। साथ ही, भारतीय युवा शक्ति की मूल प्रतिभा को नई दिशा देकर आगे बढ़ाने के काम में मदद के लिए देशभर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान, अनेक आईआईटी, आईआईएम और आईटीआई विकसित किए जा रहे हैं।

भारत जैसे सांस्कृतिक और भाषायी विविधता वाले विकासशील देश में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने वालों और रोज़गार तलाशने वालों के बीच संतुलन बनाए रखने की चिंता लंबे अर्से से चली आ रही है क्योंकि हमारे देश में 90 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के अलावा दोनों वर्गों में हुई वास्तविक वृद्धि आंकने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़े भी हैं जो दर्शाते हैं कि 2017 के बाद से 3 करोड़ से भी अधिक औपचारिक रोज़गारों के नाम जुड़े हैं। श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करने के पीछे स्पष्ट मंशा यह भी थी कि असंगठित क्षेत्र के लिए भी सुरक्षा प्रदान की जाए और बेरोज़गारी तथा पेंशन लाभ कराए जाएं। इसने अनौपचारिक क्षेत्र में रोज़गार वृद्धि मापने के लिए संख्यात्मक मानदंडों को भी समन्वित करके अधिक भरोसेमंद बनाया है।

2014 में भारत ने लगभग 4000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया था और 2022 में भारत द्वारा 15000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया जा चुका है। भारत ने नवाचारों के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ही तेजी से प्रगति की है। इस जबरदस्त कामयाबी का पता 'वैश्विक नवाचार इंडेक्स' देखने से लगता है क्योंकि जिस नवाचार सूची में 2015 में भारत का नाम 81वें स्थान पर था वहीं 2022 में भारत इस सूची में 40वें स्थान पर पहुँच गया।

रोज़गार उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, चाहे वे बड़े निर्माण उद्योग हों या मझौले निर्माण उद्योग, और इन दोनों उद्योगों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से लगातार लाभ मिल रहा है; रोज़गार के अवसर जुटाने की क्षमता से शुरू होकर निर्माण का आधार व्यापक बनाने, भारतीय बाजार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती निर्भरता और मांग बढ़ने और उसके आधार पर अधिक अवसर और रोज़गार बढ़ने तक यही हो रहा है। 2021-22 में सरकार ने पीएलआई योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया था

ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव से उबर सके तथा अधिक टिकाऊ और भरोसेमंद आपूर्ति शृंखला मॉडल विकसित किए जा सकें।

जीवन स्तर सुधारने और जीवन को सुगम बनाने के सरकार के दो लक्ष्यों का देश के युवाओं के जीवन और उनकी क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लीवरेज टेक्नोलॉजी और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि के लिए सरकार के प्रयासों के कारण बुनियादी ढांचे के विकास की गति में तेजी आई है। मेट्रो, रेलवे और सड़क संपर्कों के तेज विकास से अनेक रोज़गार योजनाओं के तहत रोज़गार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।

समावेशी शिक्षा तक पहुँच

भारत प्राचीनकाल से ही ज्ञान का केन्द्र रहा है और समाज की ऐसी धारणा है कि युवाओं की आकांक्षाओं-अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सार्थक और प्रभावी शिक्षा प्रणाली होना जरूरी है। हर भारतीय मां अपने बच्चों को उत्तम श्रेणी की शिक्षा दिलाना चाहती है। इस भावना को ध्यान में रखकर ही सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से शिक्षा सुधारों के नए युग का सूत्रपात किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नई राष्ट्रीय नीति (एनईपी) लागू करना जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया भी है। इसमें नए दौर के कौशल पर जोर दिया जा रहा है और विद्यार्थियों को अपने तरीके से पढ़ने-सीखने का मौका दिया जाता है।

इस नीति को लागू करने के लिए भारतीय युवाओं को समाधान पर मुख्य ध्यान केंद्रित रखने वाले तथा चुस्त-सतर्क और जीवन की वास्तविकताओं को झेलते हुए चुनौतीपूर्ण हालात का मुकाबला करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार बनाना होगा। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्कूलों में अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान में दक्षता अर्जित करने पर जोर देना होगा तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की संख्या पर अंकुश लगाने के प्रयास करने होंगे। उच्च शिक्षा को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए अनेक विषय पढ़ाने का विकल्प खुला रखना होगा और पाठ्यक्रम में शामिल होने या उसे छोड़कर जाने के भी कई विकल्प देने होंगे। नीति में बाल्यावस्था में विशेष देखरेख करना, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, आकलन और परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और व्यवस्था का व्यापक विस्तार करना भी शामिल है।

2014 में देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई तथा इस प्रकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने कार्यरत और स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 'एम्स' की संख्या भी तिगुनी कर दी है। साथ ही, 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (एनएमसी) लागू हो गया और यह आयोग देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च नियामक बन गया। एनएमसी से मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही भी आई है।

सभी देख पा रहे हैं कि सुधारों को कार्यरूप देने पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। 2014 में देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई तथा इस प्रकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने कार्यरत और स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 'एम्स' की संख्या भी तिगुनी कर दी है। साथ ही, 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (एनएमसी) लागू हो गया और यह आयोग देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च नियामक बन गया। एनएमसी से मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही भी आई है।

शिक्षा क्षेत्र के लक्ष्य को विस्तार दिया गया है जिससे ऐसी पक्की व्यवस्था हो सके कि 'कोई भी छूट न जाए' या 'कोई भी पिछड़ा न रह जाए।' अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभाशाली बच्चों को उत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल (ईएमआरएस) खोले गए हैं। 2004 से 2014 की अवधि में करीब 90 ईएमआरएस के लिए मंजूरी दी गई थी। 2014 के बाद से 686 ईएमआरएस मंजूर किए गए हैं जो दस वर्ष पहले की संख्या से पांच गुणा ज्यादा हैं। हर वर्ष एक आईआईटी और एक आईआईएम भी जुड़ा है और अक्तूबर, 2022 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 723 से बढ़कर 1,043 हो गई है और हम देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का सपना साकार होते देख रहे हैं। इसी प्रकार नवोदय विद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है। हर बच्चे तक उत्तम शिक्षा की सुविधा पहुँचाने के लगातार भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं।

ऐसे प्रमुख संस्थानों तक पहुँच उपलब्ध कराने में अक्सर धन की व्यवस्था बड़ी अड़चन बन जाती है। स्कूल स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए कम ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने और छात्रवृत्ति कार्यक्रम का विस्तार करने से शिक्षा तक पहुँच अब आसान हो गई है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि योग्य और प्रतिभावान विद्यार्थियों को यह फिक्र नहीं करनी होगी कि उनके परिवार वाले उनकी पढ़ाई का बोझ कैसे संभालेंगे।

जीवन में सुगमता-नई वास्तविकता

आधुनिक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के बेरोकटोक उपलब्ध होने से जीवन स्तर सुधारने की दिशा में सार्थक प्रभाव हुआ है। इससे

देश के सबसे दूरदराज वाले भागों में भी शैक्षिक, व्यावसायिक और उद्यमिता के बीच सामंजस्य लाने में बहुत मदद मिली है। सरकार ने ऐसे स्पष्ट और ठोस उपाय किए हैं जिनका करोड़ों युवाओं पर सार्थक और रचनात्मक प्रभाव हुआ है और हर विकास कार्यक्रम के मूल में जीवन की सुगमता ही मुख्य आधार है।

2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए है, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराके उनके घरों को धुएँ की समस्या से छुटकारा दिलाया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना लागू करके यह सुनिश्चित हो गया है कि देश के 99 प्रतिशत से अधिक घरों में बिजली पहुँच चुकी है और युवाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। स्वच्छता अब युवाओं की जीवनशैली का हिस्सा बन चुकी है। देश को खुले में शौच की बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के अंतर्गत 1.34 लाख से ज्यादा गांवों को 'खुले में शौच से मुक्त' यानी ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। इसका मतलब है कि इन गांवों में ठोस और तरल कचरे को उठाने, उसे उपचारित करने और फिर इस्तेमाल योग्य बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे ग्रामीण भारत का वातावरण तो सुधर ही रहा है और जनस्वास्थ्य के लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं, साथ ही हमारे युवाओं का गौरव भी बढ़ रहा है। जब जल जीवन मिशन शुरू किया गया था तो उस वक्त देश के कुल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को ही पीने के पानी के लिए नल के कनेक्शन उपलब्ध थे। आज, 10.75 करोड़ (56 प्रतिशत) से अधिक परिवारों को सीधे नल से पीने के साफ पानी की सुविधा मिल रही है। निजी स्वामित्व वाला मकान होने से आत्मविश्वास बढ़ता है और गरीबी दूर होने का संकेत भी मिलता है। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए गए हैं तथा इनके निर्माण कार्य में ही कई समुदायों ने कौशल हासिल कर लिया और युवाओं को रोज़गार भी मिले हैं । जल जीवन मिशन के अंतर्गत खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक जैसे काम सीखकर रोज़गार पाने में मदद मिली है।

उड़ान जैसी योजना से कनेक्टिविटी की पक्की व्यवस्था हो गई है जिससे विमान यात्रा किफायती हो गई है और लोग इसका फायदा पा रहे हैं। साथ ही, युवाओं को नई बातों ओर परिस्थितियों की जानकारी मिलने लगी है। राजमार्गों, रेलमार्गों और शहरी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार से भारत के युवाओं को अपनी दक्षता और उत्पादकता बढ़ाकर क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद मिली है।

स्वास्थ्य जीवनशैली पर सरकार के जोर देने से युवाओं को सीधे लाभ मिल रहा है। फिटनेस और खेलकूद स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कुंजी हैं। युवाओं में खुद को फिट और चुस्त-दुरुस्त रखने की सोच जगाने के उद्देश्य से अगस्त, 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट (स्वस्थ भारत अभियान) शुरू किया गया था। खेलों इंडिया कार्यक्रम के जरिए युवाओं में बचपन से ही खेलकूद में रुचि जगाने की पहल की गई है जिसमें बड़ी सफलता मिल रही है। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर प्रतिभावान युवाओं का चयन करके उन्हें 8 वर्ष के लिए 5 लाख रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है।

आगे का रास्ता

स्वामी विवेकानंद ने सही कहा था, "मुझे सौ ऊर्जावान युवा दे दो, मैं भारत में क्रांतिकारी बदलाव ला दूँगा।" आज भारत के युवा कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, संचार, अक्षय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, कृत्रिम मेधा और अन्य अनेकानेक क्षेत्रों में नवाचार और किफायती समाधान खोज चुके हैं।

देश के युवा ही भारत के स्वप्न को साकार करने का बीड़ा उठाकर उसे नई ऊंचाई पर पहुँचा सकते हैं। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की सौवीं वर्षगांठ मनाएगा तो देश के युवा उसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर सही अर्थों में विकसित देश बनाने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। सरकार ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने युवाओं को शिक्षा, कौशल और बढ़िया स्वास्थ्य देने के साथ भाईचारे और सर्वजन हिताय जैसे मूल्यों का भी विकास करने की कई पहल शुरू की हैं। जहां भारत अपना भाग्य बनाने में लगा है वहीं हमें अपने युवाओं के सामर्थ्य और उनकी ऊर्जा के विकास की दिशा में पूरी लगन से प्रयासरत रहना है। ■

नेहरू युवा केन्द्रों की गतिविधियां

- नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) 2018 से ही देश भर में पोषण माह कार्यक्रम को लागू करने में एक प्रमुख भागीदार रहा है। जिला नेहरू युवा केन्द्र संबंधित जिलों के प्रशासन, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से राष्ट्रीय युवा कोर-नेशनल यूथ कॉर्प्स (एनवाईसी) और युवा क्लबों को प्रेरित करते रहे हैं कि वे ग्रामीणों को कुपोषण, संतुलित आहार के महत्व और पारंपरिक भोजन के बारे में जागरूक करें।
- एनवाईकेएस ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर 947 जिला, 5661 प्रखंड और 23782 ग्राम स्तरीय योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें कुल 9.88 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया।
- संगठन ने विश्व साइकिल दिवस 2022 के मौके पर 35 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में तथा 75 प्रतिष्ठित स्थलों पर साइकिल रैलियों का आयोजन किया। कुल 8.06 लाख किलोमीटर की इन रैलियों में 123149 साइकिलिस्टों ने शिरकत की।
- एनवाईकेएस ने राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 पर रन फॉर यूनिटी से संबंधित 68364 गतिविधियां आयोजित कीं। कुल एक करोड़ किलोमीटर की इन दौड़ों में 19.71 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया।
- संगठन ने 8 से 14 अगस्त 2022 तक आइकॉनिक सप्ताह मनाया। इस दौरान उसने देश भर में आइकॉनिक स्थलों पर 7458 स्वच्छता गतिविधियां चलायीं। इन गतिविधियों के तहत 7047 तिरंगा यात्राएं आयोजित की गयीं और 57074 औषधीय पौधे लगाये गये।
- 2022 में एनवाईकेएस ने 437 जिला युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किये। युवा उत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 1.31 लाख युवाओं ने भागीदारी की। हर युवा उत्सव में छह खंड थे: युवा कलाकार शिविर- पेंटिंग, युवा लेखक शिविर- कविता, छायाचित्र प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक पर्व- सामूहिक कार्यक्रम और युवा संवाद - 2047 का भारत।